हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

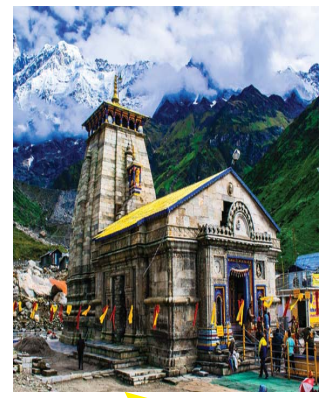

वर्ष:5 अंक:40 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, शनिवार, 14 फरवरी 2026

सेवा तीर्थ विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने तथा जनता की सेवा करने के संकल्प का प्रतीक: मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ और अन्य सरकारी कार्यालयों के नये परिसर कर्तव्य भवन -1 और कर्तव्य भवन- 2 के उद्घाटन को विकसित भारत की यात्रा में ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा है कि यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नये आरंभ का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये भवन विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने तथा जनता की सेवा करने के संकल्प का प्रतीक है। ये नये परिसर भारत की जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं, यहां जो फैसले लिये जायेंगे वह 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। सरकारी भवनों तथा प्रमुख मार्गों के नाम बदलने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने का निर्णय भर नहीं है बल्कि यह सत्ता के मिजाज

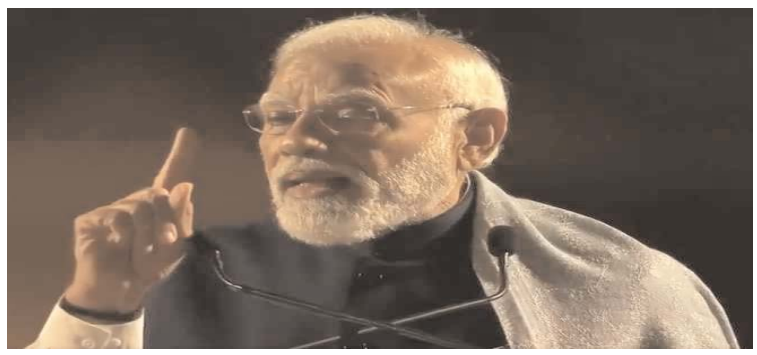

को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 विकसित राष्ट्र का लक्ष्य विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है और इसे पूरा करने के लिए हमारा हर निर्णय सेवा की भावना से प्रेरित होना चाहिए। मोदी ने शुक्रवार को यहां इन भवनों के उद्घाटन के बाद उपस्थिति जन समुदाय को संबोधित किया और ब्रिटिश काल में बने नार्थ और साउथ ब्लाक भवनों को ब्रिटिश साम्राज्य की सोच का प्रतीक बताते हुए कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में यह बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढे। उन्होंने कहा , 'हम आज एक नया इतिहास बनता देख रहे हैं। यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नये आरंभ का साक्षी बन रहा है।

विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है और इस दिन लिये गये संकल्प में विजय अवश्य प्राप्त होती है। हम विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं तथा अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आर्शीवाद हमारे साथ है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली इमारतों में अहम निर्णय लिये गये और महत्वपूर्ण नीति बनी लेकिन ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतीक थी और इनका उद्देश्य देश को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। उन्होंने कहा कि जब 1911 में देश की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली किया गया तो इसका निर्माण ब्रिटिश सम्राट की सोच और जरूरत को ध्यान में रखकर किया गया था। नॉर्थ और साउथ ब्लाक को ऊंचाई पर जानबूझकर बनाया गया जिससे कि और कोई इमारत इनकी बराबरी न कर सके। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से गुलाम भारत की जमीन पर ब्रिटिश साम्राज्य की सोच उतारनी थी। उन्होंने कहा कि इसके उलट सेवा तीर्थ जमीन से ज्यादा जुड़ा है पुरानी इमारतें जहां ब्रिटिश सोच को लागू करने के लिए थी वहीं सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नये परिसर भारत की जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं, यहां जो फैसले लिये जायेंगे वह 140 करोड जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

एक नजर

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाई

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंचायत और नगर पालिका चुनावों पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को स्वीकार कर लिया और चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया 31 मई, 2026 तक या उससे पहले पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरक्षण सूची को 31 मार्च, 2026 तक अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाए। महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) अनूप रतन ने बताया कि शीर्ष न्यायालय ने एसएलपी स्वीकार कर ली है और राज्य में पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ा दी है।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने राज्य को 28 फरवरी तक आरक्षण सूची जारी करने और 30 अप्रैल, 2026 से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें राज्य के कई हिस्सों में भारी हिमपात , सड़क अवरोध और आपदा संबंधी व्यवधानों के कारण उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया गया था। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। यह भी बताया गया कि दूरस्थ और बर्फ से ढके क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण पूर्व निर्धारित समय सीमा का पालन करना मुश्किल था।

याचिका में आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित प्रश्न भी उठाए गए, जो हिमाचल प्रदेश में अभी भी लागू है। राज्य ने यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में चुनाव अस्थायी रूप से स्थगित किए जा सकते हैं, और केंद्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और राज्य पंचायती राज अधिनियम के बीच संभावित कानूनी विरोधाभास की ओर इशारा किया। राज्य की दलीलों को सीमित रूप से स्वीकार करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा से आगे एक महीने का अतिरिक्त समय दिया, लेकिन यह भी कहा कि चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किए जाने चाहिए। राज्य में 3,577 पंचायतों और 73 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं। वर्तमान में इनमें से कई संस्थाओं का प्रबंधन प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने हिमाचल प्रदेश में निर्वाचित स्थानीय शासन की बहाली के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 09 मार्च तक के लिए स्थगित

नयी दिल्ली। संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही 09 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गयी। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 01 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया गया जिसकी प्रति उसी दिन राज्यसभा के पटल पर रखी गयी थी। पहले चरण के तहत दोनों सदनों की 13-13 बैठकें हुईं। लोकसभा में इस दौरान विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिला जिससे सदन का काफी काम प्रभावित हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न के बराबर हुई तथा प्रधानमंत्री के जवाब के बिना उसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लंबी चर्चा के बाद उसे पारित किया गया जिसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर दिया और उनके भाषण के दौरान विपक्ष ने बहिर्गमन किया। दोनों सदन में बजट पर आम चर्चा हुई जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर दिया। दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गयी। दूसरे चरण की कार्यवाही 09 मार्च को शुरू होगी जिसमें मंत्रालय वार बजट आवंटनों पर चर्चा होगी और वित्त विधेयक, अनुदान मांगों और उनसे जुड़े विनियोग विधेयक को स्वीकृति देने के साथ बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य, उत्तराखंड की उल्लेखनीय प्रगति: त्रिवेन्द्र सिंह रावत

पथ प्रवाह, नई दिल्ली।

सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि 8 फरवरी 2026 तक यू-विन (-WIN) पोर्टल पर देशभर में 11.12 करोड़ बच्चों और 3.78 करोड़ गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म देश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को पारदर्शी, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने वर्ष 2025 में देशभर में 8.01 करोड़ लाभार्थियों को यू-विन पर पंजीकृत कर क्यूआर कोड आधारित डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में 3,65,348 गर्भवती महिलाएं और 9,51,444 बच्चे -WIN पोर्टल पर पंजीकृत हैं और वर्ष 2025 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान राज्य में 7,71,381 लाभार्थियों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान -

WIN पोर्टल से देशभर में 29.42 करोड़ एसएमएस रिमाइंडर संदेश भेजे गए, जिससे लाभार्थियों को आगामी खुराकों की समय पर जानकारी मिल सकी। -WIN पोर्टल के माध्यम से 'शून्य खुराक' (Zero Dose) बच्चों की डिजिटल पहचान और मैपिंग भी की जा रही है। फ्रंट-लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित बच्चों को पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर उनका नियमित टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि U-WIN को वर्तमान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), पोषण ट्रैकर और सेफवैक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वित और समग्र प्रबंधन संभव हो सका है। सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन 'डिजिटल इंडिया' और 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में -WIN के माध्यम से टीकाकरण कवरेज में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित हुई है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरक मॉडल बन सकता है।

श्री रावत ने कहा कि अन्य बड़े राज्यों की तुलना में सीमित भौगोलिक और जनसंख्या आधार के बावजूद उत्तराखंड में पंजीकरण और डिजिटल प्रमाणपत्र निर्गमन की यह संख्या दर्शाती है कि राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना और जमीनी स्तर पर टीकाकरण अभियान प्रभावी ढंग से संचालित हो रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु तकनीक आधारित यह पहल दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है।

13 और क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की बदलेगी सूरत: डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर के 13 और प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जायेगा। जर्जर हो चुके इन विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण किया जायेगा, साथ ही कुछ विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित किये जायेंगे। जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा 274 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। उक्त विद्यालयों में निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। विद्यालयों में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर खासी संजीदा है। खासकर प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शैक्षणिक महौल के साथ ही उच्चकोटि की शिक्षा मिल सके। डॉ. रावत ने बताया कि सरकार प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में बच्चों के लिये सभी भौतिक संसाधन उपलब्ध करा रही है साथ ही ऐसे विद्यालय जिनके भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनका पुनर्निर्माण करा रही है। इसी

कड़ी में प्रदेश के चार जनपदों देहरदून, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं टिहरी के 13 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, वृहद मरम्मत कार्य एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं के लिये 274.20 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। शीघ्र ही उक्त राशि विद्यालयों को आवंटित कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जनपद देहरादून में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चान्दपुर में वृहद मरम्मत कार्य के लिये 10.80 लाख तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय सावड़ा में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिये 11.50 की लाख स्वीकृत दे दी है। इसी प्रकार पिथौरागढ़ जनपद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय किमटा को 17.50 लाख तथा कवाधार में मरम्मत कार्य के लिये 18.26 लाख स्वीकृत किये हैं। रूद्रप्रयाग जनपद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौना दानकोट, सेमलता, किमाणा, भुनका वल्ला तथा झुण्डोली में मरम्मत कार्य व कक्षा-कक्ष निर्माण के लिये 14-14 लाख स्वीकृत किये हैं। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय डुंग्रा एवं कोलू भन्नू में भवन पुनर्निर्माण के लिये 40.30-40.30 लाख मंजूर किये हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय डोभासौड़ में 32 लाख तथा टिहरी जनपद में प्राथमिक विद्यालय सुनारगांव के भवन पुनर्निर्माण के लिये 33.62 लाख स्वीकृत किये हैं। इसके साथ ही उक्त विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिये ग्रामीण निर्माण विभाग, मण्डी परिषद तथा पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। शीघ्र ही उक्त धनाराशि विद्यालयों को आंवटित कर दी जायेगी। डा. रावत ने बताया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी, इसके लिये विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं साथ ही निर्माण कार्य नियम समय पर पूरा करने को भी कहा गया है।

बेरोजगार युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग को प्राथमिकता से कराएं ऋण उपलब्धः मयूर दीक्षित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद के बेरोजगार युवाओं, किसानो एवं कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वरोजगार परख योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता से उपलब्ध कराते हुए तथा बैंकों को विभिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए प्रेषित किए गए आवेदन पत्रों को सभी बैंक प्राथमिकता से स्वीकृत करते हुए आवेदनकर्ता को ऋण उपलब्ध कराना सुनश्चित करे यह निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक में उपस्थित बैंक प्रबंधकों को दिए। बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पाया कि कई बैंकों के शाखा प्रबन्धक/ प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए,जिसपर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए लीड बैंक अधिकारी को संबंधित बैंक प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए, उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तथा विभिन्न योजनों के लंबित आवेदन पत्रों को संबंधित

अधिकारी आपसी समन्वय के साथ उनका निस्तारण करते हुए लंबित आवेदन पत्रों के आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे,इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं ढिलाई न बरती जाए।

बैंकों को लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

ऋण जमा अनुपात (C D Ratio) की समीक्षा करते हुए 40 प्रतिशत से कम ऋण जमा अनुपात वाले बैंक शाखाओं को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध करना सुनिश्चित करे जिससे कि बैंक अपना लक्ष्य हासिल कर सके। उन्होंने सभी विभागों एवं बैंक प्रबंधकों से अपेक्षा की है की उनके द्वारा जो भी डेटा वेब साइट पर जो भी डेटा /अपलोड किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी

इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक दिनेश गुप्ता ने विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी से अवगत कराते हुए कहा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जनपद में 31 दिसंबर 2025 तक कुल 2915817 बचत खाते खोले जा चुके है तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारंभ से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 860856 व्यक्तियों को बीमा किया जा चुका है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत जनपद में योजना के प्रारंभ से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 28215 व्यक्तियों का बीमा किया जा चुका है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद में योजना के प्रारंभ से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 195734 व्यक्तियों को जोड़ा जा चुका है।

उद्यान अधिकारी का रोका वेतन

बैठक में पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि उद्यान विभाग द्वारा बैंकों को प्रेषित किए गए आवेदन पत्रों की धीमी प्रगति एवं लक्ष्य पूर्ण न करने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला उद्यान अधिकारी का माह फरवरी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

साइबर क्राइम पर ग्राहकों को करें जागरूक

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंक प्रबन्धकों कहा कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे है तथा ग्राहकों को अपने जाल में फंसा रहे है,इसके लिए उन्होंने ग्राहकों को जागरूक करने के निर्देश दिए, जिसके लिए उन्होंने एसएमएस, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

बैठक में मोजूद रहे ये अधिकारी

बैठक में डीडीएम नाबार्ड अखिलेश डबराल, निदेशक आरसीटी शिव कुमार, महाप्रबंधक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी, जिला कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग गरिमा मिश्रा गोपाल कुमार, आरएफसी अभिषेक कुमार सहित संबंधित अधिकारी विभिन बैंकों के शाखा प्रबन्धक /प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

एक नजर

हरिद्वार पुलिस ने दुष्कर्म के एक और आरोपी पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बीती 7 फरवरी को पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किये थे। पुलिस के मुताबिक दिनाँक 07.02.2026 को वादिनी/पीडिता के द्वारा कोतवाली रूडकी पर तहरीर बाबत घटना प्रतिवादी मेहरबान पुत्र मकसूद निवासी ग्राम जौरासी कोतवाली रुडकी जनपद हरिद्वार द्वारा वादिया को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाना व वादिया के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना व अपने दोस्तो दानिश पुत्र सुक्का व अब्दुल रहमान उर्फ दुल्ला पुत्र जमील निवासी गण जौरासी थाना रुडकी हरिद्वार के द्वारा वादिया की अश्लील वीडियो बनाना के सम्बन्ध मे दी गयी थी जिसके आधार पर कोतवाली रूडकी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की संगीनता को देखते हुये तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली रूडकी को आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रूडकी द्वारा गठित किया गया टीम के द्वारा मुखबिरान को मामूर किया गया दो आरोपियों को पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी दानिश पुत्र भारू उर्फ सुकू निवासी ग्राम जोरासी कोतवाली रुडकी हरिद्वार को उसके मस्कन से पकडा गया।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से, परीक्षा केंद्रों के पास लागू हुई निषेधाज्ञा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ष्टक्चस्श्व) की दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है जो 10 अप्रैल 2026 तक संपन्न होगी। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने बताया कि परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेद्याज्ञा लागू की गई है।

नगर क्षेत्र हरिद्वार में परीक्षा केंद्रों सैन्टमेरी सीनियर सैकण्डरी स्कूल ज्वालापुर हरिद्वार (81027), दा विजडम ग्लोबल स्कूल निकट जूर्स कन्ट्री ज्वालापुर हरिद्वार (81636), गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार (81462), महाऋषि विद्या मन्दिर जगजीतपुर लक्सर रोड़ हरिद्वार (81444), शांति मैमोरियल पब्लिक स्कुल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार (81565), शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार (81169), डी0ए0वी0 सैंच्यूरी पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर (81059), अचीवर होम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार (81587) केंद्रों पर संपन्न करायी जायेगी।

परीक्षा को नकल विहीन, बाधा रहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की गई है।

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने बताया कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।

पौडी को हराकर पिथौरागढ़ ने जीती फुटबाल प्रतियोगिता

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार में मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी (राज्य स्तरीय प्रतियोगिता) खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत आयोजित अंडर-19 बालक वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में रोमांच अपने चरम पर रहा। सेमीफाइनल से लेकर फाइनल मुकाबले तक खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पिथौरागढ़ की टीम ने बेहतरीन रणनीति और तालमेल का परिचय देते हुए 2-1 से जीत दर्ज कर फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया। दूसरे सेमीफाइनल में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल आमने-सामने थे। इस मुकाबले में पौड़ी गढ़वाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों

टीमें बराबरी पर रहीं, जिसके बाद निर्णय पेनल्टी शूटआउट से हुआ। रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में पिथौरागढ़ ने 5-4 से जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में टिहरी गढ़वाल ने नैनीताल को पराजित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को मेडल एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर सभी खिलाड़ियों प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों को बधाई दी।

कार्यक्रम में खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग एवं व्यायाम प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक तथा अन्य अधिकारी सहित क्षेत्रवासी एवं खेलप्रेमी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानून और अधिकारों की दी जानकारी

आदर्श सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में छात्र-छात्राओं को निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं से कराया अवगत

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आदर्श सदन इंटर कॉलेज, बहादुरपुर जट में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को कानून संबंधी अधिकारों, कर्तव्यों तथा सरकार द्वारा संचालित निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई।

मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर तथा असहाय व्यक्तियों को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय सबका अधिकार है और कोई भी निर्दोष व्यक्ति केवल संसाधनों के अभाव में दंडित न हो, इसके लिए प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं संस्थानों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, कानूनी कर्तव्यों और नए कानूनों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और उन्हें अपने संवैधानिक एवं वैधानिक

अधिकारों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपस्थित अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता शिविरों से विद्यार्थियों को कानून, यातायात नियमों, महिलाओं के अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आग्रह किया कि वे शिविर में प्राप्त जानकारियों को अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि व्यापक स्तर पर जागरूकता का प्रसार हो सके।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर जितेंद्र कुमार, विकास यादव, सुरेंद्र सिंह, सुदेश चौहान, अरुणा यादव एवं वीर सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। जागरूकता शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों में कानून के प्रति समझ और सजगता विकसित करने का सार्थक प्रयास किया गया।

एक नजर

मिशन सेफ हरिद्वारः सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, यातायात पुलिस जागरूकता मुहिम

पथ प्रवाह, हरिद्वार। यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक यातायात द्वारा यातायात पुलिस की टीम गठित की गई। जिनके द्वारा सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा माह के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एडिशनल टीएसआई प्रदीप कुमार सिंह, कांस्टेबल दीपक चमोली के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यातायात नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, कोहरे के समय रिफ्लेक्टर बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन को निर्धारित यातायात नियमों के अनुरूप सुरक्षित रूप से चलाने, सड़क पर स्वयं एवं अन्य राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ऑडियो-वीडियो माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ट्रैफिक साइन ट्रैफिक सिग्नल लाइट गोल्डन ऑवर गुड्स सेमीरिटन आदि अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इंडस्ट्री कंपनी सिडकुल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उक्त जानकारी को अत्यंत उपयोगी एवं जीवन रक्षक बताते हुए यातायात नियमों का पूर्ण पालन करने का संकल्प लिया गया तथा हरिद्वार यातायात पुलिस टीम का प्लांट हेड दीपेश बिष्ट द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

कांवड़ यात्रा में हरिद्वार पुलिस ने ड्यूटी भी, सेवा भी का दिया संदेश

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शारदीय कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सेवा भाव से निरंतर कार्य किया जा रहा है। जनपद में आगमन करने वाले शिवभक्त कांवड़ियों के सुरक्षा एवं सुविधा हेतु व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इसी क्रम में कोतवाली श्यामपुर पुलिस द्वारा कांवड़ मार्ग पर चल रहे श्रद्धालुओं को सूक्ष्म जलपान वितरित किया गया तथा उनकी कुशलक्षेम पूछी गई। पुलिस कर्मियों द्वारा विनम्र व्यवहार एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कांवड़ियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई। वहीं, यातायात निरीक्षक द्वारा चिड़ियापुर जंगल क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर कांवड़ियों से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन के संबंध में फीडबैक लिया गया, ताकि व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा आमजन से भी सहयोग एवं यातायात नियमों के पालन की अपील करती है।

11 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा नशा तस्कर

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को सफल बनाने हेतु एसएसपी हरिद्वार नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में कोतवाली बहादराबाद व हरिद्वार की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक- 12-02-2026 को दौराने चैकिंग नहर पटरी संस्कृत विद्यालय के पीछे बहादराबाद से अभियुक्त अकरम पुत्र मोहब्बत निवासी मस्जिद वाली गली कस्बा बहादराबाद थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार को 11 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है।

बहुउद्देशीय शिविर में 1755 लोगों को किया गया योजनाओं से लाभान्वित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में विकासखंड भगवानपुर के न्याय पंचायत भलस्वागाज राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनों से 1755 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से 410 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। इस शिविर में 2165 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग।

आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 65 समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें 36 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया, शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशराज कर्णवाल, उपाध्यक्ष, (राज्यमंत्री स्तर) समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा कुल 65 समस्याएं दर्ज कराई गई। पानी की टंकी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत विभाग के बिल, जलभराव, चकरोड़, साफ-सफाई तथा राजस्व भूमि से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवसियो की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए और जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे।

इस अवसर पर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, राज्यमंत्री शोभाराम प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा देवी सिंह राणा, पूर्व सलाहकार सीएम नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष संदीप रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष विराट गोयल, खंड विकास अधिकारी आलोक गार्गेय सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

एचआरडीए ने अवैध व्यवसायिक निर्माण किया सील

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण ने ज्वालापुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर किए जा रहे अनाधिकृत व्यवसायिक निर्माणों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार, ज्वालापुर हरिद्वार में पीएसी गेट के सामने, टिहरी विस्थापित क्षेत्र में राजकुमार द्वारा लगभग 20म50 वर्गफुट क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा था। नियमानुसार आवश्यक अनुमति न होने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया। इसी क्रम में दूसरी कार्रवाई ज्वालापुर हरिद्वार में रेलवे फाटक से पहले, चंदवानी फर्नीचर के समीप की गई। यहां मेघा अरोड़ा द्वारा लगभग 25म50 वर्गफुट क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य के लिए मानचित्र स्वीकृति नहीं ली गई थी। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए टीम ने तत्काल प्रभाव से भवन को सील कर दिया। अभियान के दौरान संबंधित अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आगे न बढ़ाया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कांवड़ मेला व शिवरात्रि के मद्देनज़र सघन चेकिंग अभियान, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

पथ प्रवाह, हरिद्वार

शारदीय कांवड़ मेला एवं महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद पुलिस एवं प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धार्मिक आस्था के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में कांवड़िए एवं श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए भगवान शिव के मंदिरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा मेला मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। दोपहिया व चारपहिया वाहनों की सघन जांच के साथ-साथ बिना नंबर प्लेट, संदिग्ध गतिविधियों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरों एवं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। पुलिस द्वारा होटल, धर्मशाला एवं किराए के मकानों में ठहरने वाले व्यक्तियों का सत्यापन अभियान भी तेज किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित समय के अनुसार प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या कंट्रोल रूम को दें। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखें। जनपद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेला एवं शिवरात्रि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी धार्मिक आस्था का निर्वहन कर सकें।

संपादकीय

वंदेमातरम का सम्मानः राष्ट्रीय आत्मा की पुर्नस्थापना

भारत की सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और राष्ट्रभावना की धड़कनों में यदि कोई गीत सबसे गहराई से गूंजता है, तो वह है – वंदे मातरम। संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद विद्यालयों और सरकारी कार्यक्रमों में इसे पुनः संस्थागत सम्मान देने का निर्णय न केवल एक प्रशासनिक आदेश है, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता के पुनर्स्मरण का ऐतिहासिक क्षण भी है। यह निर्णय देश की उस भावधारा को पुनर्जीवित करता है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को जनांदोलन बनाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पहल के लिए निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। विद्यालयों में प्रतिदिन छह अंतरों के साथ निर्धारित धुन और 3 मिनट 10 सेकंड की समयावधि में वंदेमातरम् का गायन, और प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम में इसे अनिवार्य रूप से शामिल करना, राष्ट्रगौरव की भावना को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह स्पष्ट व्यवस्था कि जहां जन गण मन और वंदेमातरम् दोनों गाए जाएं, वहां कार्यक्रम की शुरुआत वंदेमातरम् से तथा समापन जन गण मन से हो – राष्ट्रीय मर्यादा और परंपरा के संतुलन का सुंदर उदाहरण है।

वंदेमातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का घोष था। 19वीं शताब्दी के अंत में रचित यह गीत क्रांतिकारियों की आवाज बना। विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे युवाओं के लिए यह प्रेरणा, ऊर्जा और आत्मबल का स्रोत था। 'वंदे मातरम' का उद्घोष ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। यह वही स्वर था जिसने भारत की मिट्टी को 'माता' के रूप में प्रतिष्ठित किया और राष्ट्रभक्ति को भावनात्मक ऊंचाई दी।

आज के दौर में जब वैश्वीकरण और डिजिटल संस्कृति के बीच युवा पीढ़ी तेजी से बदलते परिवेश में आगे बढ़ रही है, ऐसे में राष्ट्रीय गीतों और प्रतीकों के प्रति सम्मान का संस्कार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यालयों में प्रतिदिन वंदेमातरम् का गायन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम बन सकता है। जब छात्र-छात्राएं एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगीत गाएंगे, तो उनमें अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना सुदृढ़ होगी।

यह निर्णय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। लंबे समय तक वंदेमातरम् सीमित अवसरों तक सिमट कर रह गया था। अब इसे नियमित रूप से सार्वजनिक जीवन में स्थान मिलने से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत के बीच संतुलन बनाए रखने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इससे किसी प्रकार की भ्रम या विवाद की संभावना कम होती है और दोनों की गरिमा सुरक्षित रहती है। यह निर्णय भावनात्मक होने के साथ-साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी सुविचारित प्रतीत होता है।

वंदेमातरम् भारत की आत्मा की आवाज है। यह गीत केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि उस चेतना का प्रतीक है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया। आज जब इसे पुनः सम्मानपूर्वक दैनिक जीवन में स्थान दिया जा रहा है, तो यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी है।

राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव को सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह कदम ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य है। अब आवश्यकता है कि इसे केवल आदेश तक सीमित न रखकर भावनात्मक रूप से आत्मसात किया जाए – क्योंकि वंदेमातरम् गाने से अधिक महत्वपूर्ण है, उसे हृदय में स्थान देना।

वैलेंटाइन डे प्यार के उत्सव का नया बाजार

हर्षवर्धन पान्डे

पिछले कुछ समय से ग्लोबलाइज्ड समाज में प्यार भी ग्लोबल ट्रेंड का हो गया है। आज जहाँ इजहार और इकरार करने के तौर तरीके बदल गए हैं वहीँ इंटरनेट के इस दौर में प्यार भी बाजारू हो चला है। पहली बार शहरी चकाचौंध से इतर प्यार का यह उत्सव एक बड़ा बाजार को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हर जगह वैलेंटाइन की संस्कृति पसरती जा रही है। आज युवा भी इसकी गिरफ्त में पूरी तरह से नजर आते है तभी तो शहरों से लेकर कस्बो तक वैलेंटाइन का जलवा देखते ही बनता है। आलम यह है ये बड़ा उत्सव बन चुका है जो भारतीयों में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है।

वैलेंटाइन के चकाचौंध पर अगर दृष्टि डालें तो इस सम्बन्ध में कई किस्से प्रचलित हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की माने तो यह वैलेंटाइन अथवा वलेंतिनस नाम के तीन लोगों को मान्यता देता है जिसमें से दो के सम्बन्ध वैलेंटाइन डे से जोड़े जाते है लेकिन बताया जाता है इन दो में से भी संत वैलेंटाइन खास चर्चा में रहे। कहा जाता है संत वैलेंटाइन प्राचीन रोम में एक धर्म गुरू थे। उन दिनों वहाँ पर क्लाउडियस दो का शासन था। उसका मानना था अविवाहित युवक बेहतर सैनिक हो सकते हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में उन्हें अपनी पत्नी या बच्चों की चिंता नही सताती। अपनी इस मान्यता के कारण उसने तत्कालीन रोम में युवको के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया।

किन्दवंतियो की मानें तो संत वैलेंटाइन के क्लाउडियस के इस फेसले का विरोध करने का फैसला किया। बताया जाता है कि वैलेंटाइन ने इस दौरान कई युवक युवतियों का प्रेम विवाह करा दिया। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फासी की सजा दे दी। कहा जाता है संत के इस त्याग के कारण हर साल 14 फरवरी को उनकी याद में युवा वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 1260 में संकलित की गई ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वॉराजिन नामक पुस्तक में भी सेंट वेलेंटाइन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार रोम में तीसरी शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस के अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम होती है। उसने फरमान जारी किया कि उसका कोई सैनिक या अधिकारी विवाह नहीं करेगा। संत वेलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया। उन्हीं के आह्वान पर अनेक सैनिकों और अधिकारियों ने विवाह किए। कैथोलिक चर्च की एक अन्य मान्यता के अनुसार एक दूसरे संत वैलेंटाइन की मौत प्राचीन रोम में ईसाईयों पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने के दरमियान हो गई। यहाँ इस पर नई मान्यता यह है ईसाईयों के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले इस संत की याद में ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। एक अन्य किंदवंती के अनुसार वैलेंटाइन नाम के एक शख्स ने अपनी मौत से पहले अपनी प्रेमिका को पहला वैलेंटाइन संदेश भेजा जो एक प्रेम पत्र था। उसकी प्रेमिका उसी जेल के जेलर की पुत्री थी जहाँ उसको बंद किया गया था। उस वेलेंनटाइन नाम के शख्स ने प्रेम पत्र लिखा फ्रॉम यूअर वेलेंनटाइन । आज भी यह वैलेंटाइन पर लिखे जाने वाले हर पत्र के नीचे लिखा रहता है। क्लॉडियस ने 14 फरवरी को संत वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया। तब से उनकी स्मृति में प्रेम दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि सेंट वेलेंटाइन ने अपनी मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया व जेकोबस को एक पत्र लिखा, जिसमें अंत में उन्होंने लिखा था तुम्हारा वेलेंटाइन।

भारतीय राजनीति की सशक्त और संवेदनशील आवाज़ थी सुषमा स्वराज

सुरेन्द्र शर्मा

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की उन विरल हस्तियों में से थीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, वाक्पटुता, संवेदनशीलता और कार्यकुशलता से जनमानस में विशेष स्थान बनाया। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत, कुशल प्रशासक और करुणामयी नेता थीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की और विशेष रूप से भारत की विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ऐतिहासिक माना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है।।

सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। उनके पिता श्री हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, जिससे बचपन से ही उनके भीतर राष्ट्रसेवा की भावना विकसित हुई। उन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन में वे एक उत्कृष्ट वक्ता और सक्रिय छात्रनेता रहीं। वे कई बार 'सर्वश्रेष्ठ वक्ता' का पुरस्कार जीत चुकी थीं, जिससे उनकी भाषण कला का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सुषमा स्वराज ने बहुत कम आयु में राजनीति में प्रवेश किया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वे हरियाणा विधानसभा की सदस्य बनीं और 27 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गईं। उस समय वे देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री थीं। यह उनकी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी जुड़ी रहीं।

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद सुषमा स्वराज ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रहीं। वर्ष 1998 में वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, हालांकि उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। हर पद पर उन्होंने दक्षता और ईमानदारी से कार्य किया।

सुषमा स्वराज की पहचान एक ओजस्वी वक्ता के रूप में भी रही। संसद में उनके भाषण तार्किक, प्रभावशाली और मर्यादित होते थे। वे विपक्ष में रहते हुए भी अपनी बात मजबूती से रखती थीं और सत्ता में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती थीं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान दक्षता से बोलती थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण विशेष रूप से सराहा गया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को मजबूती प्रदान की।

नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह पद केवल सरकार की आलोचना करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने, नीतियों की समीक्षा करने और जनता की आवाज़ को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने का दायित्व भी निभाता है। सुषमा स्वराज ने वर्ष 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने अपनी वाक्पटुता, तर्कशक्ति, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से इस पद की गरिमा को नई ऊँचाई दी

नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज की सबसे बड़ी पहचान उनकी प्रभावशाली और मर्यादित वक्तृत्व शैली थी। वे अपने भाषणों में तथ्यों, तर्कों और उदाहरणों का संतुलित उपयोग करती थीं। उनकी भाषा में तीखापन तो होता था, लेकिन वह कभी व्यक्तिगत कटाक्ष या असंसदीय शब्दों तक नहीं पहुँचता था। वे सरकार की नीतियों की कठोर आलोचना करती थीं, परंतु सदैव संसदीय मर्यादा का पालन करती थीं।

जब भी संसद में कोई महत्वपूर्ण विधेयक या मुद्दा चर्चा के लिए आता, सुषमा स्वराज विपक्ष की ओर से स्पष्ट और सुविचारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थीं। उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता था, क्योंकि वे केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करती थीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव भी देती थीं।

भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर भूमिका 15वीं लोकसभा के दौरान केंद्र में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला (कोलगेट), कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आदि। इन मुद्दों पर सुषमा स्वराज ने विपक्ष की ओर से सशक्त आवाज़ उठाई।

उन्होंने संसद में इन मामलों की निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही की मांग की। कई बार संसद में गतिरोध की स्थिति बनी, लेकिन उनका तर्क था कि जब तक गंभीर आरोपों पर स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक सरकार को जवाब देना होगा। उनके नेतृत्व में विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग उठाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया।

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा

सुषमा स्वराज का मानना था कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की पक्षधर थीं। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या किसी आपात स्थिति से जुड़ा मुद्दा आता, वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती थीं

उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद जैसे विषयों पर उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, साथ ही आवश्यक प्रश्न भी उठाए। यह संतुलन उनके परिपक्व नेतृत्व का प्रमाण था।

बांग्लादेश में बीएनपी की वापस

कांतिलाल मांडोत

बांग्लादेश की राजनीति में लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्पष्ट जीत और उसके नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने न केवल ढाका की सत्ता संरचना को बदला है, बल्कि नई दिल्ली की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को भी सक्रिय कर दिया है। चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट किया है कि मतदाताओं ने स्थिरता, अनुभव और राजनीतिक विरासत को प्राथमिकता दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस परिवर्तन का भारत-बांग्लादेश संबंधों और विशेष रूप से बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक रूप से गहरे जुड़े रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर हाल के वर्षों तक दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार, जल बंटवारे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग किया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध अपेक्षाकृत प्रगाढ़ रहे। सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग और पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट सुविधाओं ने द्विपक्षीय भरोसे को मजबूत किया। ऐसे में सत्ता परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से एक नए संतुलन की तलाश के रूप में देखा जा रहा है।

तारिक रहमान की वापसी और उनकी पार्टी की बहुमत के साथ जीत ने यह संकेत दिया है कि बांग्लादेशी मतदाता एक मजबूत राजनीतिक केंद्र चाहते हैं। हालांकि बीएनपी का अतीत भारत के साथ संबंधों को लेकर मिश्रित रहा है, लेकिन वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियाँ किसी भी नई सरकार को व्यावहारिक कूटनीति अपनाने के लिए बाध्य करती हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्यात, विशेषकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, और क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर है। भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार और रणनीतिक साझेदार है। इसलिए टकराव की राजनीति के बजाय सहयोग की राह चुनना नई सरकार के हित में होगा। जहाँ तक हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न है, यह विषय केवल आंतरिक राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि द्विपक्षीय संवेदनशीलता का भी हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव और छिटपुट घटनाएँ सामने आती रही हैं, जिन पर भारत में चिंता व्यक्त होती रही है। नई सरकार के लिए यह एक कसौटी होगी कि वह कानून-व्यवस्था को निष्पक्ष और कठोर बनाए रखे तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव पर त्वरित कार्रवाई करे। बीएनपी की जीत को कट्टरपंथी राजनीति की अस्वीकृति के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। यह संकेत देता है कि मतदाता अतिवादी एजेंडे से दूरी चाहते हैं। यदि नई सरकार इस जनादेश को समझते हुए समावेशी शासन का मॉडल अपनाती है, तो हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बन सकता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक स्पष्टता से सुनिश्चित होती है। तारिक रहमान के सामने अवसर है कि वे अपनी सरकार को आधुनिक, आर्थिक सुधारों पर केंद्रित और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देने वाली सरकार के रूप में स्थापित करें। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो नई दिल्ली की नीति आमतौर पर व्यक्तियों के बजाय संस्थागत संबंधों पर आधारित रही है। चाहे ढाका में अवामी लीग की सरकार रही हो या अब बीएनपी की, भारत का प्रयास रहेगा कि सहयोग के मौजूदा ढांचे को बनाए रखा जाए। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दे दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े हैं। यदि नई सरकार इन क्षेत्रों में निरंतर सहयोग बनाए रखती है, तो द्विपक्षीय विश्वास बना रहेगा। हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल अक्सर भावनात्मक रूप ले लेता है, लेकिन इसका समाधान संस्थागत मजबूती में निहित है। बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करता है, और वहां की न्यायपालिका तथा नागरिक समाज सक्रिय रहे हैं। यदि सरकार इन संस्थाओं को स्वतंत्र और प्रभावी बनाए रखती है, तो किसी भी समुदाय के साथ अन्याय की संभावना कम होती है। भारत भी राजनयिक माध्यमों से अपनी चिंताओं को रचनात्मक ढंग से रख सकता है, जैसा कि अतीत में होता आया है।

आर्थिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत-बांग्लादेश व्यापार लगातार बढ़ा है, और ऊर्जा सहयोग, रेलवे संपर्क तथा जलमार्ग विकास जैसी परियोजनाएँ दोनों देशों को परस्पर निर्भरता की दिशा में ले जा रही हैं। नई सरकार यदि आर्थिक सुधारों और निवेश को प्राथमिकता देती है, तो उसे क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता होगी। यह स्थिरता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक शांति से सीधे जुड़ी है। इसलिए व्यावहारिक राजनीति की मांग है कि सरकार किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक अस्थिरता को बढ़ावा न दे।

तारिक रहमान के लिए यह भी एक अवसर है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश की सकारात्मक छवि को पुनर्स्थापित करें। लंदन से लंबे निर्वासन के बाद उनकी वापसी और भारी जनसमर्थन ने उन्हें एक नई वैधता दी है। यदि वे इस वैधता का उपयोग समावेशी शासन और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंधों के लिए करते हैं, तो भारत-बांग्लादेश संबंधों में नई ऊर्जा आ सकती है। भारत भी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ढाका के साथ रचनात्मक संवाद को प्राथमिकता देगा। बीएनपी की जीत को केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि बांग्लादेशी लोकतंत्र की एक नई परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। हिंदू समुदाय की सुरक्षा इस परीक्षा की एक महत्वपूर्ण कसौटी होगी। यदि नई सरकार कानून के शासन को सर्वोपरि रखती है और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव पर सख्ती से नियंत्रण करती है, तो न केवल हिंदू सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंध भी अधिक परिपक्व और स्थिर बनेंगे।

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ बना जनविश्वास का सबसे बड़ा अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में घर-घर पहुंच रही सरकार

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान सरकार को सीधे जनता के द्वार तक ले जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रहा है।

व्यापक जनभागीदारी और अभूतपूर्व सफलता

प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक कुल 630 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इन कैंपों में अब तक 4,92,395 नागरिकों ने प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं एवं सुझाव दर्ज कराए।

केवल आज आयोजित 8 कैंपों में ही 8,372 नागरिकों ने प्रतिभाग किया, जो इस अभियान के प्रति जनता के बढ़ते

विश्वास को दर्शाता है।

शिकायत निवारण में तेज़ी

अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 48,093 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 32,282 शिकायतों का निस्तारण मौके पर अथवा त्वरित कार्यवाही के माध्यम से किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रशासनिक तंत्र पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

प्रमाण पत्र एवं योजनाओं का लाभ

विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों हेतु अब तक 68,983 आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न सरकारी योजनाओं से अब तक 2,74,069 नागरिकों को लाभान्वित किया गया। केवल आज ही 5,014 नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, जहां अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।

जनपदवार सक्रियता

हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली सहित सभी जनपदों में कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया।

विशेष रूप से हरिद्वार और देहरादून में आज बड़ी संख्या में प्रतिभागिता दर्ज की गई, जो इस अभियान की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘सरकार जनता के द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और हर नागरिक को सम्मानपूर्वक न्याय मिलेगा।’ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिया जाए।

सुशासन की ओर मजबूत कदम

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की जनकल्याणकारी सोच और उत्तरदायी शासन प्रणाली का सशक्त उदाहरण है। यह अभियान न केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता को भी सुदृढ़ कर रहा है। प्रदेश सरकार जनसेवा के अपने संकल्प के साथ इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विज़न को गति, आवास एवं नगर विकास योजनाओं में पारदर्शिता

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीक आधारित सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में आवास विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण

सचिव आवास ने डिस्पेन्सरी रोड स्थित राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स में संचालित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, नगर नियोजन विभाग तथा रेरा कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, जनसुविधाओं, लंबित प्रकरणों और सेवा वितरण प्रणाली का गहन अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा बैठक में समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव आवास/मुख्य प्रशासक एवं आयुक्त के रूप में डॉ. आर. राजेश कुमार ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप योजनाओं का प्रभाव धरातल पर

दिखाई देना चाहिए। विकास कार्यों में गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जानी चाहिए।

‘ईज एप’ को और अधिक सरल व एकीकृत बनाने के निर्देश

सचिव आवास ने ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली ‘ईज एप’ का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस एप को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के साथ एकीकृत किया जाए ताकि पूरे राज्य में एक समान डिजिटल व्यवस्था लागू हो सके। उन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए चैटबॉट विकसित करने तथा एक सप्ताह के भीतर एप को और सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के सुझावों सहित विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

लैण्ड पूलिंग एवं टाउन प्लानिंग स्कीम को प्राथमिकता

डॉ. आर. राजेश कुमार ने लैण्ड पूलिंग स्कीम एवं टाउन प्लानिंग स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए जहां इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुनियोजित शहरी विस्तार के लिए इन योजनाओं का प्रभावी संचालन अत्यंत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सचिव आवास ने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं। उन्होंने अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु बैंकर्स के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।

पार्किंग परियोजनाओं और डिकंजेशन पॉलिसी पर सख्ती

सचिव आवास ने पार्किंग परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संचालन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने डिकंजेशन एंड रिडेवलपमेंट पॉलिसी को शीघ्र तैयार कर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने को कहा, ताकि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव और अव्यवस्थित निर्माण की समस्या का समाधान किया जा सके।

जीआईएस आधारित महायोजनाओं पर जोर

महायोजनाओं के निर्माण में अनिवार्य रूप से जीआईएस प्रणाली लागू करने तथा यूसेक के माध्यम से उसके सत्यापन के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही सुनियोजित और दीर्घकालिक विकास संभव है।

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध कार्यसंस्कृति अपनाने पर विशेष बल दिया।

आलयम आवासीय योजना का स्थलीय निरीक्षण

समीक्षा बैठक के उपरांत सचिव आवास ने सहस्त्रधारा रोड स्थित मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की आलयम आवासीय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण गुणवत्ता एवं आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर वित्त नियंत्रक परवीन कौर, संयुक्त सचिव गौरव कुमार चटवाल, वरिष्ठ नगर नियोजक शालू थिन्ड, अधीक्षण अभियन्ता राजन सिंह, अधिशासी अभियन्ता सुनील कुमार, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता विनोद कुमार चौहान, कार्यक्रम प्रबंधक कैलाश चन्द्र पाण्डेय एवं पीएमयू के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही- डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को सुनियोजित, सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल शहरी विकास का आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की अवधारणा केवल आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शी प्रशासन, तकनीक आधारित सेवाएं और जनसुविधाओं का सुदृढ़ विस्तार भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम, जीआईएस आधारित महायोजनाएं, ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति और आवासीय योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों को सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। विभाग का लक्ष्य है कि शहरीकरण संतुलित, पर्यावरण-संवेदनशील और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हमारे किसानों के हक में, राहुल उन्हें भड़का रहे हैं: गोयल

नयी दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को पूरी तरह देश के किसानों के हित में बताते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर इस समझौते को लेकर किसानों को गुमराह करने और उन्हें आपस में भिड़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौते से देश के किसानों को फ़ायदा होगा, खेती के सामान का ज़्यादा निर्यात होगा और उनके उत्पादों मांग बढ़ेगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और किसानों की खुशहाली होगी। उन्होंने किसानों को समझौते को लेकर आश्वस्त किया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं तथा समझौते में देश के किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा गया है। गोयल ने आज तड़के जारी एक बयान में कहा, ‘ राहुल गांधी जी को मिथ्याचार की आदत है। उन्हें भारत माँ या हमारे किसानों और युवाओं की भलाई की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आज (कल) जारी एक वीडियो में, झूठ बोलने और बेबुनियाद आरोप लगाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गांधी ने गुरूवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि अमेरिका के साथ हुआ समझौता देश के किसानों के हित में नहीं है इसलिए वह इसके खिलाफ किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। गोयल ने बयान में कहा, ‘ वह (श्री गांधी) अपनी मनगढ़ंत बातों से हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे अन्नदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कभी हमारी मातृभूमि की परवाह नहीं की, और न ही हम उनसे भारत के मजबूत और खुशहाल भविष्य के लिए काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। ‘

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण, बीएलओ आउटरीच अभियान,बूथ लेवल एजेंट्स की शत प्रतिशत नियुक्ति के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि आगामी एसआईआर की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश में बीएलओ द्वारा आउटरीच अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 79 प्रतिशत मैपिंग की जा चुकी है। उन्होंने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में बीएलए के सहयोग से मैपिंग प्रक्रिया और तेजी से की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि वर्तमान में राजनैतिक दलों द्वारा 15437 बूथ लेवल एजेंट्स की जा चुकी है। जिसमें भाजपा द्वारा 7165, कांग्रेस द्वारा 7968, बीएसपी द्वारा 117, सीपीआई (एम) द्वारा 187 बीएलए नियुक्त किए गए हैं,

इसके अतरिक्त आप और एनपीपी द्वारा अभी एक भी बीएलए अबतक नियुक्त नहीं किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से फरवरी माह तक शत प्रतिशत बीएलए नियुक्त करने की अपील की। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित बीजेपी से राजकुमार पुरोहित, विरेंद्र वल्दिया, कांग्रेस पार्टी से मनोज रावत, अमेंद्र बिष्ट,सीपीआई (एम) से अनंत आकाश,बीएसपी से सुरेंद्र जजारिया उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जनता के साथ टी स्टॉल पर लिखी विकास की नई पटकथा

चौखुटिया एवं तड़ागताल का किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने चौखुटिया एवं तड़ागताल क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण एवं निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तड़ागताल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया गया। जिलाधिकारी से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कहा कि तड़ागताल को झील के रूप में विकसित करने से न केवल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में भी ठोस पहल संभव होगी।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने तड़ागताल में निर्माणाधीन सड़क कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिनमें आबादी के बीच स्थित बिजली के खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग प्रमुख रही। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। भ्रमण निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्थानीय चाय स्टॉल पर बैठकर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के पश्चात जिलाधिकारी ने माता अगनेरी देवी मंदिर में दर्शन कर मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु कार्य कराए जाने के निर्देश प्रदान किए।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने चौखुटिया में अगनेरी एवं बाखली खेल मैदान का भी निरीक्षण किया तथा खिलाड़ियों से संवाद किया। जिलाधिकारी ने चौखुटिया में एक खेल मैदान को सुविधा युक्त मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खेल एवं पर्यटन सुविधाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। इन दोनों क्षेत्रों के समन्वित विकास से स्थानीय युवाओं को अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ आधार मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सुनील कुमार, बीडीओ ममता कार्की सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

गोदान फिल्म देखने पहुंचे संत, भारत माता और गौ माता के जयघोष से गूंजा सिनेमा हॉल

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

रोशनाबाद स्थित पेंटागन मॉल में भारतीय संस्कृति एवं गौ माता पर आधारित फिल्म 'गोदान' का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर रवींद्र पुरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरिद्वार के विभाग प्रचारक राकेश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एवं साधु-संत बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

फिल्म प्रदर्शन के दौरान 'भारत माता की जय', 'गौ माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से पूरा पिक्चर हॉल गूंज उठा। उपस्थित जनसमूह ने फिल्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और गौ संरक्षण के संदेश को सराहा।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि 'गोदान' फिल्म भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान रखने वाली गौ माता के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि गाय का पालन-पोषण एवं संवर्धन हर दृष्टि से लाभकारी है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और जिस घर में गौ माता का पालन होता है, वहां सुख-समृद्धि एवं स्वास्थ्य का वास होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि फिल्म में दिए गए संदेशों को घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि गौ पालन और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने फिल्म के निर्देशक एवं कलाकारों को इस विषय पर सार्थक प्रयास के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस फिल्म को करमुक्त किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देखकर लाभान्वित हो सकें। इस निर्णय के लिए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और समय-समय पर गौ रक्षा के लिए हिंदू समाज ने बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि गौ संवर्धन और संरक्षण को जनआंदोलन का रूप दिया जाए। फिल्म में दर्शाए गए दृश्य समाज की वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है, उसी प्रकार गौ माता का दूध समस्त प्राणियों के पोषण का आधार है। ऐसी फिल्में सनातन संस्कृति और धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम में महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, जिला महामंत्री संजीव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, निपेंद्र चौधरी, सीमा चौहान, विशाल गर्ग, अभिनव चौहान, तेलूराम प्रधान, उज्ज्वल पंडित, प्रीति गुप्ता, जसबीर बसेड़ा, रेशु चौहान, धर्मेंद्र चौहान, अरविंद कुशवाहा, उमेश पाठक, मनोज शर्मा, देवेंद्र चौधरी, मनोज गौतम, रितु ठाकुर, गुड्डी कश्यप, कैलाश भंडारी, सुशील पवार, संजीव कुमार, पंकज बागड़ी, प्रताप प्रधान, बिंदर पाल, वासु पाराशर, सूबे सिंह, नागेंद्र राणा, मोनू त्यागी, अमित चौहान सहित सैकड़ों साधु-संत एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शहरी विकास सचिव नितीश झा ने किया कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को बैठक में दिये निर्देश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुंभ कार्यों को पूरा करने की डेड लाइन तय करने के बाद कुम्भ मेला-2027 को लेकर शासन-प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शहरी विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव नितेश कुमार झा ने शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचकर कुम्भ मेला क्षेत्र में प्रस्तावित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुम्भ मेला-2027 को सुव्यवस्थित एवं भव्य रूप से आयोजित करने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं।

उन्होंने कुंभ क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष बल देते हुए कहा कि साधु-संतों एवं श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही सभी संबंधित विभागों को सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सचिव श्री झा ने पंतद्वीप चमगादड़ टापू सेक्टर में ?172.01 लाख की लागत से निर्माणाधीन अंतःस्रोत कूप का निरीक्षण किया तथा कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम के अभियंताओं को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कूप से होने वाली जलापूर्ति हेतु स्थायी पाइपलाइन बिछाई जाए, ताकि भविष्य के मेलों में भी इसका उपयोग हो सके। उन्होंने पंतद्वीप क्षेत्र में कुम्भ के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर भी गतिविधियां आयोजित करने की कार्ययोजना बनाने को कहा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बैरागी कैंप में ?526.81 लाख की लागत से 1500 के.एल. क्षमता के ओवरहेड टैंक एवं नलकूप निर्माण कार्य, दक्षद्वीप क्षेत्र में ?172.01 लाख की लागत से निर्माणाधीन अंतःस्रोत कूप, शिवालिक नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य तथा पथरी रौ नदी पर ?966.61 लाख की लागत से निर्माणाधीन पुल की प्रगति का भी स्थलीय निरीक्षण किया। बैरागी कैंप, दक्षद्वीप, धीरवाली पार्किंग स्थल सहित विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर उन्होंने प्रस्तावित अस्थायी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हरकीपैड़ी को जोड़ने वाले मार्गों एवं पुलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने समुचित मरम्मत, सौंदर्यीकरण तथा सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खुले स्थलों के सौंदर्यीकरण तथा श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त स्थानों पर सुव्यवस्थित शौचालय स्थापित करने पर भी जोर दिया। मेला नियंत्रण भवन स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करते हुए सचिव ने इसे और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए।

डामकोठी में आयोजित समीक्षा बैठक में मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ मेले से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थायी प्रकृति के सभी कार्य अविलंब प्रारंभ कर निर्धारित समय पर पूर्ण किए जाएं तथा अस्थायी कार्यों से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। आईटीडीए, पुलिस विभाग एवं टीसीआईएल के प्रतिनिधियों के साथ कुम्भ क्षेत्र में सीसीटीवी एवं ड्रोन सर्विलांस की प्रस्तावित कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करते हुए उन्होंने पूर्व में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता का ऑडिट कराने तथा कुम्भ क्षेत्र के प्रमुख स्थलों को निगरानी के दायरे में लाने हेतु संशोधित तकनीकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

सचिव श्री झा ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर कुम्भ मेला को लेकर प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्टेशन पर दूसरी ओर से भी यात्रियों के आवागमन हेतु ओवरब्रिज निर्माण तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एकीकृत योजना तैयार करने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार, एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, आईटीडीए के अपर निदेशक तीर्थपाल सिंह, एएसपी कुंभ विपिन कुमार, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, उप मेलाधिकारी आकाश जोशी व मंजीत सिंह गिल तथा हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ऋतु खण्डूडी भूषण के कोटद्वार आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत

लालढांग–चिल्लरखाल रोड को मिली न्यायिक स्वीकृति के बाद उमड़ा जनसैलाब, क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल

पथ प्रवाह, कोटद्वार

उच्चतम न्यायालय द्वारा लालढांग-चिल्लरखाल रोड के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण को अनुमति मिलने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद कोटद्वार पहुंचीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण का नगर में भव्य एवं अभूतपूर्व स्वागत किया गया।

नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्रवासी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारी एवं उद्यमी स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिला। विशेष रूप से हजारों महिलाओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया।

फूलमालाओं, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। उपस्थित जनसमूह ने लालढांग-चिल्लरखाल रोड को न्यायिक स्वीकृति दिलाने हेतु उनके निरंतर प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया गया, जिससे समारोह का उत्साह और भी बढ़ गया।

अपने संबोधन में ऋतु खण्डूडी भूषण ने क्षेत्र की जनता के स्नेह एवं समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा अधिवक्ताओं का विशेष धन्यवाद किया, जिनकी प्रभावी पैरवी से सर्वोच्च न्यायालय से कोटद्वार के पक्ष में यह महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त हुआ।

उन्होंने गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी का भी विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सतत निगरानी एवं सक्रिय सहयोग से यह कार्य संभव हो सका। साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल एवं वन विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि समयबद्ध प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के कारण वन क्षेत्र से गुजरने वाली इस सड़क को अब निर्माण की स्वीकृति मिल सकी है।

अध्यक्ष ने बताया कि सड़क निर्माण हेतु शीघ्र ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का पालन करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लालढांग-चिल्लरखाल रोड क्षेत्र के लिए जीवनरेखा सिद्ध होगी। इसके सुदृढ़ीकरण से लगभग 18 गांवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं पर्यटन को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र मुख्यधारा से सशक्त रूप से जुड़ सकेंगे।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के समग्र एवं संतुलित विकास का संकल्प आगे भी इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा।

कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, राज्य मंत्री राजेंद्र अन्थवाल, मंडल अध्यक्ष आशीष रावत, प्रेमा खंतवाल, विकासदीप मित्तल, सुमन कोटनाला, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र नेगी, प्रमोद केष्टवाल, कमल नेगी, पार्षद राजेंद्र बिष्ट, रजनीश बेबनी, सौरव नौडियाल, रितु चमोली, कुबेर जलाल, विनोद धूलिया, मोहन सिंह नेगी, युवा मोर्चा अध्यक्ष शांता बमरारा, महिला मोर्चा शशि बाला केष्टवाल, अनु मोर्चा सुनीता देवी, प्रकाश बलौदी, गणेश अधिकारी, अनिल गौड़, राजीव डबराल, पवन गौड़, सुभाष जखमोला, पूर्व सैनिक एवं व्यापार मंडल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एक नजर

ग्राम खेड़ाजट में गोलीकांड का एक और आरोपी दबोचा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली मंगलौर पर बीती 3 फरवरी को ग्राम खेड़ाजट में हुई फायरिंग की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल पांच आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। घटना से संबंधित अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी हरिद्वार द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर को तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक से कोतवाली मंगलौर खुद टीम का हिस्सा बनते हुए नामित आरोपियों की धर पकड़ शुरू की तथा मुखवीर से व्यक्तिगत मुलाकात करते हुए मुकदमे से संबंधित आरोपियों के रिश्तेदारी आदि सभी सम्भवित स्थानो पर ताबड़ तोड़ ?दबिश दी गई परन्तु आरोपी लगातार फरार चल रहा था। जिस सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय से आरोपी के कुर्की उद्घोषणा वारण्ट प्राप्त कर चस्बा किया गया के पश्चात आरोपी को दिनांक 13-2-26 को पकडा गया।

हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में आए 2 संदिग्ध, नाजायज चाकू बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान के सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में कोतवाली रुड़की पुलिस द्वारा अलग अलग अलग अलग स्थानो से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 02 संदिग्धों को पकड़ा गया। जिनके कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किये गए। इनके खिलाफ कोतवाली रूडकी पर अलग अलग अभियोग पंजीकृत किये गये है। पुलिस के मुताबिक राहुल पुत्र रामकरण को सोनाली नदी से नहर पटरी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गौरव पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम चावमण्डी को बुचड़ी फाटक के पास यात्री सेड के पास रूडकी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ।

नशे में गढ़ी लूट की झूठी कहानी, पुलिस ने पहुंचाया जेल

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशन में आपातकालीन सेवाओं पर भ्रामक सूचना देने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्यामपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक बीती रात एक कॉलर ने 112 पर सूचना दी कि मोटरसाइकिल (P11-3904) सवार दो युवकों ने उससे 10,000 रुपये और दो मोबाइल फोन लूट लिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात्रि अधिकारी अ.उ.नि. रविन्द्र गौड तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे।कॉलर जयन्त ममगई से पूछताछ की, तो वह अत्यधिक शराब के नशे में पाया गया और अपनी क्रेटा कार (K08AJ-9955) चला रहा था। पूछताछ के दौरान वह घटना के संबंध में विरोधाभासी बयान देने लगा। स्थानीय लोगों से पूछताछ और सख्ती से जांच करने पर पता चला कि लूट की कोई घटना हुई ही नहीं थी। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने नशे की हालत में पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करा कर धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया व घटना में प्रयुक्त कार (K08AJ-9955) को एम.वी. एक्ट के तहत सीज किया गया।

जल्द पूरा होगा मुख्यमंत्री का सपना, साफ स्वच्छ हो हरिद्वार अपना

पथ प्रवाह, हरिद्वार। तीर्थ नगरी हरिद्वार को साफ स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में 3 माह से निरंतर सफाई अभियान शहर से लेकर गांव कस्बों तक चलाया जा रहा है,जिसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है।

जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों, सामाजिक संस्थाओं,धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं,व्यापार मण्डल एवं सभी गैर सरकारी, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छ सुंदर जनपद बनाने के लिए जिस तरह सभी लोगों ने 07 फरवरी को जनपद में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता की है, जिसमें कि 150 से अधिक मैट्रिक टन गीला एवं सुखा कूड़ा एकत्रित किया गया है। जिससे कि सफाई अभियान में हरिद्वार जनपद में एक मिसाल कायम की है। इस मेगा स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों का जिलाधिकारी ने हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जनपद वासियों से अपेक्षा की हैं जिस तरह से सभी लोगों ने 07 फरवरी को चलाए गए मेगा अभियान में भागीदारी की है इसी तरह सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में नियमित सफाई अभियान में भागीदारी करे, जिससे कि जनपद हरिद्वार को साफ, स्वच्छ जनपद बनाया जा सके।

बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने बताया कि शुक्रवार को बीएचईएल टाउनशिप प्रशासन विभाग द्वारा आर्य समाज मंदिर से शिव मंदिर सेक्टर 1 एवं आसपास क्षेत्र में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। खंड विकास अधिकारी नारसन ने अवगत कराया है कि आज विकास खंड नारसन क्षेत्रांतर्गत मंडोली,रायपुर,नसीरपुर आदि क्षेत्रों में साफ सफाई कराई गई ।

कंट्रोल रूम में आयी 103 शिकायतें

जिलाधिकारी के निर्देशन में स्वच्छता अभियान की सफलता हेतु सुझाव एवं शिकायत के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में अब तक 103 शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें 73 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतें निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है। नोडल अधिकारी स्वच्छता कंट्रोल रूम चंद्रकांत मणि त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए सुझाव एवं शिकायत के लिए विकास भवन में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों से संबंधित अब तक 103 शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिसमें से अब तक विभिन्न विभागों द्वारा 73 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष 30 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित है।

उन्होंने स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए किसी भी सुझाव एवं शिकायत के लिए कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 8273371714 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सुझाव एवं शिकायत दर्ज कर सकते है।

विधायक महंत दिलीप सिंह रावत बोले, सरकार की योजनाएं अब गांव-गांव तक

पथ प्रवाह, पौड़ी।

विकासखंड जयहरीखाल की न्याय पंचायत असनखेत में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली। शिविर में समस्याओं के समाधान के साथ विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में सकारात्मक वातावरण रहा।

शिविर में कुल 25 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण तत्काल मौके पर ही कर दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा 314 लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। शिविर में कुल 521 ग्रामीणों ने प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं रखीं और योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

क्षेत्रीय विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने शिविर में उपस्थित रहकर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उपजिलाधिकारी शालिनी मौर्य ने कहा कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से सतत संवाद बनाए रखें और शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता बरतें। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, पशुपालन, राजस्व, वन विभाग सहित कुल 23 विभागीय स्टॉल लगाए गए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रणवीर सजवाण, ज्येष्ठ उप प्रमुख सुरेंद्र नेगी, अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्भय सिंह, खंड विकास अधिकारी रवि सैनी सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

एक नजर

अवैध स्मैक के साथ 1 आरोपी दबोचा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन- 2025 के तहत जनपद को नशा मुक्त करने व नशा तस्करों के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रूडकी द्वारा युवाओं की नशों में जहर घोलने वाले नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु अलग-अलग टास्क दिये गये है, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रूडकी द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ हेतु अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। उक्त क्रम में एक व्यक्ति रितिक पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना गंगनहर जिला हरिद्वार को 06.16 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकडा गया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली रूडकी पर NDPS Act का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

नहर पटरी पर हुई जानलेवा हमले की घटना का खुलासा, एक गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। झुग्गी-झोपड़ी पीठ बाजार से धनौरी मार्ग नहर पटरी के पास आपसी विवाद में मारपीट और चाकूबाजी की घटना हुई थी। जिसपर वादी निल पुत्र बलबहादुर लिम्बू ने अभियुक्त शेख कासिम के विरुद्ध उनके दोस्त अजय पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से कई वार करने के संबंध में कोतवाली पिरान कलियर में मु.अ.सं. 26/2026 धारा 109 BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष पिरान कलियर की गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शेख कासिम को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू के साथ दबोचा गया। जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है।

कप्तान के तबादले से पहले 8 चौकी प्रभारियों समेत 14 के तबादले

पथ प्रवाह,हरिद्वार। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के तबादला आदेश से पहले जनपद में 8 चौकी प्रभारियों समेत 14 दरोगाओं के तबादले किये गए हैं। इन चौकी प्रभारियों में कुछ दारोगा ऐसे है जोकि थानाध्यक्ष रह चुके हैं। रानीपुर कोतवाली के एसएसआई नितिन चौहान को लक्सर कोतवाली का एसएसआई बनाया गया है, कोतवाली मंगलौर से प्रदीप कुमार को रानीपुर कोतवाली का एसएसआई बनाया गया है। एसएसआई लक्सर के लोकपाल परमार को भिक्कमपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है। रफत अली को एसपी ग्रामीण कार्यालय में अटैच किया गया है। प्रवीण बिष्ट को मंगलौर कोतवाली की बाजार चौकी की कमान दी गई है। एसआई वीरेंद्र सिंह नेगी गंगनहर कोतवाली की अस्पताल चौकी का प्रभारी बनाया गया है। रायसी चौकी प्रभारी नीरज सिंह रावत को काली नदी चौकी प्रभारी बनाया है। बलबीर सिंह को सप्तऋषि चौकी प्रभारी बनाया गया है। अंशुल अग्रवाल को चौकी बाजार ज्वालापुर का प्रभारी बनाया गया है। कर्मवीर को तेज्जुपुर चौकी प्रभारी और थाना पथरी से अजय लाल को रायसी चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस लाइन से महिपाल सैनी को कोतवाली कनखल भेजा गया है। राकेश कुमार को कोतवाली ज्वालापुर भेजा गया है। रानीपुर से देवेंद्र सिंह को कोतवाली मंगलौर भेजा गया है। तबादला सूची में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नवीन तैनाती पर कार्य करने के लिए कहा गया है।

उत्तराखंड में 20 आईपीएस अफसरों के तबादले, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर के कप्तान बदले

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड में 20 आईपीएस के तबादला किए हैं, जिनमें 8 जिलों के एसएसपी भी बदले गए है। हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर, पिथौरागढ, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोडा के एसएसपी बदले है। इन तबादलों को कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल को देहरादून का एसएसपी बनाया है। जबकि एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को हरिद्वार का एसएसपी बनाया है। चंपावत के एसएसपी अजय गणपति कुम्भार को उधमसिंह नगर का एसएसपी बनाया है। उधमसिंहनगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना बनाया है। अभिसूचना पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय को पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी बनाया है। पिथौरागढ की एसपी रेखा यादव को चंपावत का एसपी बनाया है। रुद्रप्रयाग के एसपी अभय प्रहलाद कोंडे को पिथौरागढ़ का एसपी बनाया है। निहारिका तोमर को रुद्रप्रयाग का एसपी बनाया है। जितेंद्र कुमार मेहरा को बागेश्वर का एसपी बनाया है। हरिद्वार में ही तैनात एसपी निशा यादव को हरिद्वार में यातायात और क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को एसटीएफ का एसएसपी बनाया है। चंद्रशेखर आर घोडके को अल्मोडा का एसएसपी बनाया है। अल्मोडा के एसएसपी देवेंद्र पींचा को 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर का सेनानायक बनाया है। मनोज ठाकुर को कोटद्वार में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया है। चंद्रमोहन सिंह को अभिसूचना देहरादून भेजा है। निवेदिता कुकरेती को एसडीआरएफ का पुलिस महानिरीक्षक और प्रल्हाद नारायण मीणा को पुलिस उप महानिरीक्षक सतर्कता मुख्यालय बनाया है। यशवंत सिंह को पीटीसी नरेंद्रनगर का प्रधानाचार्य बनाया है। प्रदीप कुमार राय को सीबीसीआईडी का पुलिस अधीक्षक बनाया है।

कांग्रेस विधायकों ने की बजट सत्र अवधि बढ़ाए जाने की मांग

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आगामी उत्तराखण्ड विधानसभा के बजट सत्र की अवधि कम से कम तीन सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि सत्र की अवधि कम होने के कारण प्रदेश के ज्वलंत और जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कहा कि राज्य में विधानसभा सत्र अन्य राज्यों की तुलना में कम दिनों के लिए आयोजित होता है, जिससे 70 विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं प्रभावी ढंग से उठाने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता।विधायकों ने मांग की कि प्रश्नकाल और विधायी कार्यों के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार से स्पष्ट जवाब लिया जा सके। उनका कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदन में खुली, गंभीर और विस्तृत चर्चा आवश्यक है। ज्ञापन में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, वन्यजीवों के हमलों से हो रही जनहानि, पेयजल संकट और आपदा पीड़ितों के पुनर्वास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि हर घर नल जैसी योजनाओं के बावजूद कई इलाकों में पेयजल संकट बना हुआ है। साथ ही, पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार अब भी मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि राज्य में अब भी कई कानून उत्तर प्रदेश काल के लागू हैं, जिन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी कई जरूरी विधायी सुधार लंबित हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बजट सत्र के दौरान आवश्यक संशोधन विधेयक लाकर प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

राजकीय इंटर कॉलेज द्वारीखाल में आयोजित हुआ करियर काउंसलिंग कार्यक्रम

पथ प्रवाह, पौड़ी। विकासखण्ड द्वारीखाल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज द्वारीखाल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में लगभग 40 छात्राओं ने भाग लिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति अरोड़ा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर प्लानिंग पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

केन्द्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर लक्ष्मी रावत ने अधिवक्ता और न्यायिक सेवाओं से संबंधित करियर विकल्पों की जानकारी साझा की। उन्होंने एलएलबी सहित आवश्यक शैक्षणिक तैयारियों के साथ-साथ बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के प्रति बच्चों को जागरुक किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में करियर को लेकर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना था। विशेषज्ञों ने छात्राओं से उनके करियर लक्ष्यों को निर्धारित करने और आत्मविश्वास के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में शिक्षक राजेश भारद्वाज, शिवरतन नेगी, सीमा एवं विनोद भारद्वाज, डॉ. ऋषि रावत (चिकित्साधिकारी), राकेश रावत (डाक सहायक), नीरज कुमार (शाखा प्रबंधक, एसबीआई), राजमोहन नेगी (पीटीए अध्यक्ष), गीता देवी (सुपरवाईजर), राकेश सिंह (कनिष्ठ सहायक), एनएनएम जितेन्द्र रावत आदि ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित करियर विकल्पों और अनुभव साझा किए।

लीसा विदोहन से ग्रामीण आर्थिकी को मिलेगी मजबूती, वनाग्नि रोकथाम में भी मिलेगी प्रभावी सहायता

पथ प्रवाह, पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी वन प्रभाग महातिम यादव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में आगामी लीसा सत्र की तैयारियों को लेकर रेखीय विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य मार्च माह से प्रारंभ होने वाले लीसा विदोहन सत्र की पूर्व तैयारियों की समीक्षा तथा विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करना रहा।

प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि सभी उप-जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में वन पंचायतों के चुनाव समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने की आवश्यकता है, ताकि लीसा विदोहन कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि सिविल वन क्षेत्र एवं नाप क्षेत्र में वृक्ष गणना में राजस्व कार्मिकों का सहयोग आवश्यक है, जिससे लीसा निकासी की पारदर्शी एवं व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, परियोजना प्रबंधक रीप कुलदीप बिष्ट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला समूहों की भागीदारी

उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों एवं ग्रामवासियों को लीसा विदोहन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से नाप क्षेत्र से लीसा विदोहन में संबंधित उपजिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि यह पहल ग्रामीणों की आर्थिकी की रीढ़ साबित हो सकती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। 'लापता इकॉनमी' को पुनर्जीवित करने की इस पहल में जन-जागरूकता और विभागीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वनाग्नि रोकथाम में भी सहायक होगी पहल

प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि लीसा विदोहन में स्थानीय ग्रामीणों की निरंतर और सक्रिय भागीदारी वनाग्नि की रोकथाम में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। बैठक में वर्ष 1976 से प्रचलित लीसा विदोहन नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। आगामी लीसा सत्र मार्च माह से प्रारंभ हो रहा है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु यह बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

पारंपरिक रील प्रणाली के साथ -साथ अपनाई जाएगी बोर होल प्रणाली

बैठक की एक महत्वपूर्ण जानकारी यह रही कि लीसा निकालने की पारंपरिक रील प्रणाली के साथ साथ अब बोर होल प्रणाली से भी लीसा निकाला जाएगा। इससे लीसा की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी तथा चीड़ के पेड़ों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रणाली पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसहभागिता के बिना किसी भी कार्ययोजना का सफल क्रियान्वयन संभव नहीं है, इस हेतु ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 10 लाख का योगदान

पथ प्रवाह, देहरादून

लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनने और समाज के प्रति दायित्व निभाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। इसी भावना का परिचय देते हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी, निवासी वसंत विहार, देहरादून एवं मूल निवासी जहरिखाल, पौड़ी गढ़वाल, ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये की धनराशि दान की।

ब्रिगेडियर जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर चेक सौंपा। यह सहयोग पूर्व में आई दैवीय आपदाओं के दौरान राहत-बचाव कार्यों तथा आपदा से प्रभावित गरीब एवं वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सहायता के उद्देश्य से दिया गया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अनुभवी सैन्य अधिकारी होने के नाते ब्रिगेडियर जोशी की यह पहल राज्य और समाज के समग्र विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा समाज के अन्य लोगों को भी सेवा और सहयोग के लिए प्रेरित करती है।

इस अवसर पर ब्रिगेडियर एच. के. जोशी की पुत्री सुश्री शानू जोशी भी उपस्थित थीं।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्प्लैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com